मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। उन्होंने झुंझुनूं, आबू रोड और डूंगरपुर हवाई पट्टी के विस्तार के लिए निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री भजनलाल ने प्रदेश में हवाई सुविधाओं की समीक्षा की

कोटा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, झुँझुनूँ, आबू रोड, डूँगरपुर हवाई पट्टी विस्तार के निर्देश दिये

- **मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में जयपुर एयरपोर्ट की क्षमता 50 लाख से बढ़ाकर 70 लाख यात्री प्रतिवर्ष करने का कार्य तेज गति से करने के निर्देश दिये।**
- **हरियाणा से सालासर और खाटूश्याम जी हवाई सुविधा के बारे में विस्तार से चर्चा की गई।**

जयपुर, 28 अप्रेल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में हवाई सुविधाओं का विस्तार करने के लिए राज्य सरकार ने दूरगामी निर्णय लिए हैं। इससे पर्यटन, शिक्षा एवं व्यापारिक गतिविधियों में इज़ाफा होगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अपेक्षित गति मिलेगी। मुख्यमंत्री सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक हवाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्रम में कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट महत्वपूर्ण साबित होगा। इस एयरपोर्ट के विकास के लिए राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य एमओयू हो चुका है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ईएचवी लाइन शिफ्टिंग और आरआरवीपीएनएल की लाइन शिफ्टिंग के कार्य में तेजी लाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर एयरपोर्ट पर बनने जा रहे स्टेट टर्मिनल पर विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएं और टर्मिनल की बिल्डिंग के स्थापत्य में जयपुर की विरासत की झलक मिले तथा आधुनिक सुविधाएं भी विकसित हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल की क्षमता 50 लाख से बढ़ाकर 70 लाख यात्री प्रतिवर्ष की जा रही है।

शर्मा ने प्रदेश में हवाई पट्टियों के उन्नयन और विस्तार की समीक्षा की। उन्होंने झुंझुनूं, आबू रोड और डूंगरपुर हवाई पट्टी के विस्तार के लिए निर्देश दिए। साथ ही, प्रतापगढ़ और हमीरगढ़ में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइज़ेशन (एफटीओ) के कार्यों में भी गति लाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने हरियाणा से सालासर और खाटूश्यामजी के लिए हवाई सुविधा और एयर एंबुलेंस सुविधा के विस्तार के संबंध में विस्तृत चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एयर एंबुलेंस की सुविधा से दूरस्थ स्थानों के लिए आपातकालीन चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी।

बैठक में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक, मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

'हमने "टू नेशन थ्योरी" को 1947 में ही दरिया में बहा दिया था'

अब्दुल्लाह ने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष पर कटाक्ष किया, "टू नेशन थ्योरी" को पुनः उठाने पर

- **फारुख अब्दुल्लाह ने कहा कि वे पहले सदा पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में रहते थे, पर, अब वे केवल यह चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार ऐसी सख्त कार्यवाही करे, पाकिस्तान के खिलाफ कि पहलगाम जैसी हरकतें दुबारा कभी न हों।**

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 अप्रेल। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्लाह ने बेहद कठोर बयान जारी किया और इस्लामाबाद को फटकारते हुए कहा कि कश्मीरियों ने 1947 में ही द्विराष्ट्र सिद्धांत को दरिया में बहा दिया था और कह दिया था कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ नहीं जाएगा।

नैशनल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन ने कहा कि, वे हमेशा पाकिस्तान के साथ वार्ता के पक्ष में रहते थे पर अब चाहते हैं कि केन्द्र सरकार पाकिस्तान पर कड़ी कार्यवाही करे ताकि ऐसे हमले दोबारा न हों।

न्यूज़ एजेंसी के अनुसार अब्दुल्लाह ने कहा कि, मैं हमेशा पाकिस्तान के साथ वार्ता की बात करता था पर हम उन लोगों को क्या जवाब देंगे जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है? क्या हम न्याय कर रहे हैं? बालकोट नही, आज देश ऐसा एक्शन चाहता है ताकि ऐसे हमले दोबारा न हों।"

द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात करते हुए डॉ. अब्दुल्लाह ने पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया और कहा जम्मू कश्मीर के लोगों ने 1947 में दो राष्ट्र वाले सिद्धांत को ठुकरा दिया था और आज भी वो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

अब्दुल्लाह ने कहा, "हमें खेद है कि हमारा पड़ौसी यह नहीं समझता है कि उसने इंसानियत का कत्ल कर दिया है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से हम पाकिस्तान के साथ चले जाएंगे तो हमें यह गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए। हम 1947 में उनके साथ नहीं गए थे तो अब क्यूं जाएंगे? हमने उस समय ही दो राष्ट्र वाले सिद्धांत को दरिया में बहा दिया था और आज भी हम इस सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई हम सब एक हैं। हम उन्हें करारा जवाब देंगे।"

पहलगाम हमले के बाद आया फारुख अब्दुल्लाह का यह बयान पाक सेनाध्यक्ष जनरल असीम मूनीर के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने दो राष्ट्र के सिद्धांत का जिक्र किया था।

इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए 16 अप्रेल को जनरल मूनीर ने कहा था कि भारत के खिलाफ संघर्ष में पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा रहेगा।"

उन्होंने कहा, "यह हमारे गले की नस था और रहेगा, हम इसे नहीं भूलेंगे।"

उसी भाषण में उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने कहा लोग अपने बच्चों को पाकिस्तान की कहानियां सुनाएं ताकि वे यह न भूलें कि वे हिन्दुओं से अलग है।

उन्होंने पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा, आप लोग अपने बच्चों को पाकिस्तान की कहानी सुनाएं ताकि वे यह न भूलें कि हमारे पूर्वज सोचते थे कि हम हिंदुओं से हर प्रकार से अलग हैं।

'संसद का विशेष सत्र...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कि वे इन देशों में अपने रिपोर्टर भेजें, जहाँ मोदी पाकिस्तान को भला-बुरा कह सकते हैं। संसद सत्र बुलाये जाने की माँग पर, सरकार से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।

रोचक बात यह है कि कांग्रेस के अन्दर कार्यकर्ताओं और नेताओं का एक वर्ग, उस तौर-तरीके की आलोचना कर रहा है, जिस तरीके से पार्टी नेतृत्व ने मोदी सरकार को व्यापक समर्थन दिया है, किन्तु गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग नहीं की, जो कश्मीर, आन्तरिक सुरक्षा गुप्तचर विभाग के कर्ता-धर्ता हैं। पहलगाम में सुरक्षा तथा खुफिया विफलता के कारणों को लेकर सवाल क्यों नहीं किये जा रहे हैं।

एक कांग्रेस नेता ने तो यहाँ तक कह दिया कि कहीं यह नैशनल हैरल्ड केस तथा रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ केसों का परिणाम तो नहीं है। हो सकता है कि कांग्रेस अब संसद के विशेष सत्र की माँग करके, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की आलोचनापूर्ण प्रतिक्रिया का डैमेज-कन्ट्रोल कर रही हो।

बीकेयू ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आतंकवादियों और भारत विरोधी तत्वों को ताकत देते हैं। उन्होंने कहा कि देश व दुश्मनों का खात्मा ही एकमात्र उपाय है।

उन्होंने भारत विरोधी ताकतों की जाँच करने का आग्रह किया।

एन.सी.ई.आर.टी. ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भाग में छोड़े गये अध्याय भाग-2 में शामिल होंगे अथवा नहीं।

मुगल आदि राजवंशों के संदर्भ हटाये जाने की अनेक क्षेत्रों में आलोचना हुई है।

आलोचकों में विपक्षी दल भी शामिल हैं।

विपक्षी दलों ने एनसीईआरटी पर एक विशेष राजनैतिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है।

एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने गत वर्ष पाठ्य पुस्तकों से 2002 के गुजरात दंगों से सम्बंधित जानकारी हटाये जाने का बचाव किया था।

उन्होंने कहा था कि ऐसा इसलिये किया गया है ताकि हिंसा तथा संघर्ष के संदर्भों से बचा जा सके तथा "सकारात्मक नागरिक" निर्माण में मदद मिले।

इसके अतिरिक्त, नई पाठ्य पुस्तक में प्राचीन भारतीय पांडित्य एवं विद्वत्ता, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि का व्याकरण, आर्य भट्ट का खगोल विज्ञान तथा गुप्त साम्राज्य का वैज्ञानिक योगदान- के संदर्भ सविस्तार दिये गये हैं।

पाठ्य पुस्तक में, वर्ण-जाति व्यवस्था को शुरुआती सामाजिक ढ़ाँचे के रुप में प्रस्तुत किया गया है, जो कालान्तर में, और विशेषरुप से ब्रिटिश शासनकाल में, कठोर हो गई तथा असमानताएं पैदा हो गईं।

भाजपा अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया टली

पहलगाम आतंकी हमले के बाद बने हालात को देखते हुए यह फैसला किया गया है

- **अभी यह पता नहीं है कि चुनाव प्रक्रिया फिर से कब शुरु होगी।**

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पार्टी के नये राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को कुछ समय के लिए टालने का फैसला किया है।

पार्टी के सूत्रों के अनुसार, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद बने हालात को देखते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक बार फिर टाल दिया गया है। पार्टी ने जगत प्रकाश नड्डा को कुछ समय के लिए अध्यक्ष बनाये रखने का भी फैसला किया है। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कब तक के लिए टाले गये हैं, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है।

पहले बताया गया था कि भाजपा का नया अध्यक्ष अप्रैल के अंत तक या मई की शुरुआत में चुन लिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पार्टी नेतृत्व ने संगठनात्मक चुनाव को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। पार्टी महसूस करती है कि इस समय संगठन की स्थिरता और सरकार की नीति को मज़बूती से आगे बढ़ाना ज़रूरी है। ऐसे में पार्टी के आंतरिक चुनाव को फिलहाल प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। नए अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीख की घोषणा बाद में होगी।

उल्लेखनीय है कि भाजपा के संविधान के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तब तक नहीं हो सकता, जब तक आधे से ज्यादा राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे न हो जाएं। अभी तक 14 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं और बाकी राज्यों में प्रक्रिया चल रही है। नड्डा का कार्यकाल पहले ही बढ़ाया जा चुका है, और वह फिलहाल अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। नड्डा को वर्ष 2019 में भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। इसके बाद जनवरी 2020 में वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे।

देश के स्वाभिमान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कमज़ोर कर रही है। इसका डटकर मुकाबला करना है।

उन्होंने कहा कि जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेस कांफ्रेंस करने मुंबई पहुंच गए थे। संसद पर हमला हुआ तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सोनिया गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को कहा था कि हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दीजिए। जयपुर में भाजपा के एक विधायक ने माहौल बिगड़ने का काम किया। पायलट ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आव्हान किया कि, कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी मेहनत और एकजुटता से काम करेगा तो साढ़े तीन साल के बाद राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी।

सभा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी संबोधित किया, उनहोंने कहा कि पहलगाम में पाकिस्तान की शह पर आतंकी हमला हुआ। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि केवल बातें ही होंगी या काम होगा? पहलगाम में चूक कहां हुई?

सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी चैनल पर अश्लील सामग्री के प्रसारण के खिलाफ नोटिस जारी किया

ये नोटिस केन्द्र सरकार नेटफ्लिक्स, एमेजॉन प्राइम, ऑल्ट बालाजी तथा कुछ अन्य चैनल्स को दिए गए हैं

- **सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला जनहित याचिकाओं पर विचार करते हुए दिया। यह याचिका पूर्व सूचना आयुक्त उदय माहुरकर, संजीव नेवार, सुदेष्णा भट्टाचार्य, शताब्दी पांडे, स्वाति गोयल ने दायर की थी।**

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री को लेकर नियमन की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने पर सहमति जताई और कहा कि इस मुद्दे ने 'गंभीर चिंताएं' पैदा की हैं।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने केंद्र सरकार और नेटफ्लिक्स, एमेजॉन प्राइम, ऑल्टबालाजी, उल्लू डिजिटल तथा मुबी सहित प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ-साथ सोशल मीडिया जगत की दिग्गज कंपनी एक्स कॉर्प, गूगल, मेटा इंक और एप्पल को नोटिस जारी किया। इस मामले को अन्य समान लंबित याचिकाओं के साथ भी टैग किया गया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने इस बात पर जोर दिया कि याचिका प्रतिकूल नहीं थी, बल्कि सोशल मीडिया तथा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री के अनियंत्रित प्रसार के बारे में 'वास्तविक चिंता' जताई गई थी।

न्यायालय के प्रश्न का उत्तर देते हुए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्वीकार किया कि वे याचिकाकर्ताओं द्वारा उजागर की गई कुछ चिंताओं से सहमत हैं। प्रस्तुत कार्यक्रमों की सूची की समीक्षा करने के बाद, उन्होंने पाया कि नियमित शो में भी अश्लील सामग्री प्रसारित की गयी थी और कुछ कार्यक्रमों को इतना विकृत बताया कि दो सम्मानित व्यक्ति भी एक साथ बैठकर उन्हें नहीं देख सकते।

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, यह याचिका ओटीटी प्लेटफार्मों और सोशल मीडिया पर विभिन्न आपत्तिजनक अश्लील और अभद्र सामग्री के प्रदर्शन के संबंध में एक महत्वपूर्ण चिंता पैदा करती है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि सामग्री विकृति की सीमा तक जाती है। उन्होंने कहा कि कुछ और विनियमन विचाराधीन हैं।

जनहित याचिका पत्रकार एवं पूर्व सूचना आयुक्त उदय माहुरकर, संजीव नेवार, सुदेशना भट्टाचार्य मुखर्जी, शताब्दी पांडे और स्वाति गोयल द्वारा दायर की गई थी।

तहव्वुर राणा की हिरासत अवधि बढ़ी

- **26 नवम्बर को गिरफ्तार राणा की 18 दिन की हिरासत पूरी होने पर उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने फिर से उसे 12 दिन की हिरासत में भेज दिया।**

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल। दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट की एक विशेष अदालत ने सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अर्जी पर मुंबई में आतंकवादी हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा की हिरासत की अवधि 12 दिन के लिए बढ़ा दी।

मुंबई में 26 नवंबर के भयावह आतंकवादी हमलों की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार राणा को इससे पहले अदालत ने 18 दिन की रिमांड पर एनआईए को सौंपा था।

राणा को भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत अदालत की अनुमति से इसी माह विशेष विमान से नयी दिल्ली लाया गया था। एनआईए ने नयी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते ही उसे 10 अप्रैल को हिरासत में ले लिया था।

उसी शाम उसे दिल्ली की विशेष अदालत में पेश कर जांच एजेंसी ने उससे पूछताछ के लिए 18 दिन की रिमांड पर ले लिया था। रिमांड की अवधि पूरी होने पर आज उसे अदालत में पेश किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करे। वहीं, हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 14 फरवरी, 2024 को मामले का निस्तारण करते हुए हाईकोर्ट प्रशासन को कहा था कि वह प्रख्यात विधिवेत्ताओं और प्रोफेसरों की कमेटी का गठन करे। वहीं, कमेटी को कहा था कि वह अभ्यर्थियों में से किन्हीं बीस का चयन कर उनकी कॉपियों का परीक्षण करे। इस दौरान कमेटी उत्तर की लंबाई और उसे लिखने के लिए दिए गए समय को भी देखे। वहीं, पूर्व में मिले अंक व विशेषज्ञ कमेटी की ओर से दिए अंकों की तुलना करे। इसके बाद कमेटी प्रशासनिक स्तर पर निर्णय ले कि क्या पूर्व में घोषित परिणाम में संशोधन किया जाए या अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिये जाने अथवा सभी उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः: जांच की जाए। याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने इस आदेश की पालना नहीं की। याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने हाईकोर्ट प्रशासन से जवाब मांगा है। गौरतलब है कि एडीजे भर्ती-2020 में वकील कोटे के 85 पदों में से सिर्फ चार अभ्यर्थियों को पास किया गया था। वहीं साल 2024 की भर्ती में भी सिर्फ एक अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है।

राष्ट्रपति मुर्मू ने पद्म सम्मान प्रदान किए

- **राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में 71 व्यक्तियों को पद्म अवॉर्ड दिए गए। इनकी घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की गई थी।**

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 71 व्यक्तियों को सोमवार को यहां राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया।

राष्ट्रपति सचिवालय के अनुसार मुर्मु ने पहले चरण के अलंकरण समारोह में 04 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 57 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की गयी थी।

पद्म पुरस्कार विजेता मंगलवार सुबह राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पद्म पुरस्कार विजेता राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री संग्रहालय का भ्रमण भी करेंगे। समारोह में उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ , प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और पर्यावरण एव वन मंत्री भूपेन्द्र यादव तथा अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन लडाकू विमानों की खरीद पर मुहर

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच भारत और फ्रांस की सरकारों ने सोमवार को यहां फ्रांस के साथ 63 हजार करोड़ रूपये की लागत से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद के सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किये।

रक्षा मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबास्टियन लेकोर्नु ने इस सौदे पर हस्ताक्षर किये।

पाकिस्तान के 16 यू ट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल। सरकार ने भारत, भारतीय सेना और सुरक्षा एजेन्सियों के बारे में भड़काऊ, झूठे, भ्रामक और सांप्रदायिकत सद्भावना को बिगाड़ने वाली सनसनीखेज सामग्री का प्रसारण करने वाले पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

सरकारी सूत्रों ने सोमवार को बताया कि यह प्रतिबंध केन्द्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिश पर तत्काल प्रभाव से लगाया गया है। जिन यूट्यूब चैनलों प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें डॉन न्यूज, समा टीवी , ऐरे न्यूज और जियो न्यूज प्रमुख हैं। ये चैनल पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद दोनों देशों के बीच उपजी तनावपूर्ण स्थिति के मद्देनजर भ्रामक और सनसनीखेज सामग्री का प्रसारण कर रहे हैं।

सरकार ने इसके अलावा इरशाद भट्टी, बी ओ एल न्यूज, रफ्तार, द पाकिस्तान रेफरेन्स, समा स्पोर्ट्स् ,जीएनएन, उजैर क्रिकेट , उमर चीमा एक्सक्लुसीव , असमा सिराजी और मुनीब जैसे यू ट्ययूट चैनलों पर प्रतिबंध लगाया है।

'आप व्यर्थ के जोशीले, भड़काऊ भाषण देने से...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- **अतः भारत भी पाकिस्तान पर "स्विफ्ट" धड़ाधड़ "वॉर" करने के पक्ष में है, जिससे पाकिस्तान जवाबी कार्यवाही कर ही नहीं पाये। भारत को अपने ही दम पर पाकिस्तान के साथ लड़ाई के लिये तैयार रहना चाहिए और लम्बे युद्ध के रास्ते नहीं जाना चाहिए।**

यह स्पष्ट है कि उसकी सहानुभूति किस ओर है।

चीन ने पाकिस्तान में बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के निर्माण में बड़ी मात्रा में निवेश किया है। अगर गंभीर युद्ध की स्थिति आती है, तो उन सारे बुनियादी ढांचों, जो चीन के पैसों से बने हैं और जिनकी लागत अब तक पाकिस्तान ने चुकाई नहीं है, को नुकसान से बचाना चीन की प्राथमिकता होगी।

इसके अलावा, विवादित क्षेत्र कश्मीर में भी चीन की गहरी दिलचस्पी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर उसकी मुख्य ट्रांसपोर्ट लाइनें गुज़रती हैं। इस क्षेत्र में किसी भी बड़े संघर्ष से ये संरचनाएं और चीनी हित निश्चित रूप से प्रभावित होंगी। आखिरकार, इन्हीं क्षेत्रों से चीन, अरब सागर पर स्थित अपनी नई बंदरगाह सुविधाओं तक डायरैक्ट रूट बनाना चाहता है।

इस स्थिति में भारत को अनेक मोर्चों और स्तरों पर अकेले लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। अमेरिका को इस बात की ज्यादा चिंता नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के साथ क्या होता है, जब तक कि उसके टैरिफ युद्ध के परिणाम उसके लिए संतोषजनक रहते हैं। लेकिन डॉनल्ड ट्रंप का दुर्भाग्य है कि टैरिफ युद्ध के परिणाम अमेरिका के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। ट्रंप अब अपने द्वारा बनाए गए घरेलू संकटों में इस कदर उलझ गए हैं कि उनके पास दक्षिण एशिया की चिंता करने का समय नहीं है।

अगर किसी देश ने भारत के पक्ष में निर्णायक और सकारात्मक संकेत दिए हैं, तो वह रूस है। लेकिन रूस की भी अपनी समस्याएं हैं। यूक्रेन का संकट सुलझने का नाम नहीं ले रहा है और अब रूस पर ही हमले तेज हो रहे हैं। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि रूस 8 से 10 मई तक एकतरफा युद्धविराम की बात कर रहा है।

रूस ने यूक्रेन से प्रत्यक्ष बातचीत के भी कुछ आश्वासन दिए हैं। यह पहली बार है कि रूस ने ऐसा किसा है। अगर रूस यूक्रेन के संकट से कुछ हद तक मुक्त होता, तो भारत के लिए एक उपयोगी सहयोगी साबित हो सकता था।

वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक परिदृश्य की इस जटिलता में, भारत को अपनी दंडात्मक रणनीति अत्यंत बुद्धिमानी से चलानी होगी।

अगर कोई सैन्य कार्रवाई करनी है, तो भारत को इसके परिणाम और संभावित समय सीमा को लेकर पूरी तरह सुनिश्चित होना होगा। यह एक संक्षिप्त, लेकिन बेहद तीव्र और दबावकारी हमला होना चाहिए, जिससे पाकिस्तान के पास प्रतिक्रिया देने का समय ही न बचे।

इस समय ऐसी योजना बनाना अनुचित नहीं है। पाकिस्तान युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि युद्ध के लिए विशाल आर्थिक संसाधनों की ज़रूरत होती है। एक दिवालिया देश युद्ध का खर्च नहीं उठा सकता। उसके पास हथियारों के लिए पैसे भी नहीं हैं। पाकिस्तान इस समय फंड के लिए चारों तरफ हाथ फैला रहा है।

पाकिस्ततानी सेना की स्थिति शायद अब तक की सबसे कमज़ोर है, उसकी प्रतिष्ठा, सीनियर सैन्य अधिकारियों के साथ जो हुआ, और सेना की आंतरिक राजनीति के कारण बुरी तरह धूमिल हो गई है। सेना, वायुसेना और नौसेना के सीनियर मोस्ट लोगों ने स्वयं को सुविधाजनक सेवा विस्तार (सर्विस एक्स्टैंशन) दे रखे हैं। सत्ता के उच्चतम स्तर पर इस तरह की चिपक कर रहने की प्रवृत्ति ने निश्चित ही कई अधिक योग्य जूनियर अधिकारियों को निराश किया है, जो उच्च पदों पर आने की आशा लगाए हुए थे।

परस्पर जुड़ी घटनाओं और सितारों का इस तरह का क्रम भारत द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के लिए अनुकूल है। परंतु सवाल यह है कि क्या भारत इस समय इतनी बड़ी, तेज और दबदबा कायम करने वाली पहल के लिए वास्तव में तैयार है?

आईपीएल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

टिकट ब्लैक करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार करने का हवाला देते हुए कहा कि आरोपियों के पास कई टिकट बरामद हुई हैं, जो वे अधिक राशि में ब्लैक कर रहे थे। जबकि दूसरी ओर, राजस्थान रॉयल्स के उपाध्यक्ष को इसकी जानकारी ही नहीं है कि टिकट किसे बेचे गए हैं। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि आईपीएल को अन्य प्रांतों के दर्शक भी देखते हैं, जो अपना समय और धन खर्च करने के बाद भी टिकट प्राप्त करने में विफल रहे हैं। यह इस बात को दिखाता है कि टिकटों को कालाबाजारी में बेचा गया है। यह गंभीर विषय है और प्रशासन को इस तथ्य की जांच करनी जरूरी है कि मैच के टिकट अवांछित तत्वों को किसने उपलब्ध कराए और इसमें राजस्थान रॉयल्स के पदाधिकारियों की भूमिका तो नहीं है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालयः सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908